बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 173 ● नई दिल्ली ● बुधवार 09 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

आप को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, ऑफिस किराया मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विट्ठल भाई पटेल हाउस स्थित अपने ऑफिस के किराए को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्त की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. कोर्ट में आप पार्टी ने दाखिल अपनी याचिका में दावा किया है, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यरत निदेशालय ने उनकी पार्टी को आवंटित डबल सूइट कमरे का आवंटन 14 सितंबर 2024 से रद्द कर दिया. वह भी बिना कोई शो कॉज नोटिस दिए.आप को कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया.

जेलों में कट्टरपंथियों को पनपने से रोकने के लिए अमित शाह ने उठाये सख्त कदम, राज्यों को जारी की बड़ी सलाह

नई दिल्ली। इस तरह के वाकये पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं कि जेलों में बंद कट्टरपंथी दूसरे कैदियों का भी ब्रेन वॉश करके उन्हें गलत राह पर धकेल देते हैं। देखा जाये तो जेलों में कैदियों को कट्टरपंथी बनाये जाने की घटनाएं अब गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। यह प्रवृत्ति आंतरिक सुरक्षा के लिए तेजी से बढ़ा खतरा बन रही है इसलिए संकट की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस दिशा में तुरंत प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को जारी एक परामर्श में कहा गया है कि कारागारों में बंद कमजोर मानसिकता वाले व्यक्तियों में उग्र विचारधारा के प्रसार को रोकना तथा ऐसे कैदियों को मुख्यधारा में लौटाने के लिए 'डि-रेडिकलाइजेशन' की प्रक्रिया अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। देखा जाये तो कारागार एक सीमित व नियंत्रित वातावरण होता है जहाँ सामाजिक अलगाव, समूह मनोवृत्ति तथा निगरानी की सीमितता जैसी परिस्थितियाँ अतिवादी विचारों के पनपने के लिए उपजाऊ भूमि बन जाती हैं। कई बंदी, जो पहले से ही हताशा, समाज से कटाव या हिंसात्मक प्रवृत्तियों से ग्रस्त होते हैं, ऐसे माहौल में उग्रपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने चेताया है कि कुछ मामलों

अमित शाह

में कट्टरपंथी बंदी हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं– चाहे वह जेल के स्टाफ पर हमला हो, अन्य बंदियों को नुकसान पहुँचाना हो या फिर बाहरी नेटवर्क के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना हो। गृह मंत्रालय ने 'मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016' और 'मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023' का हवाला देते हुए बताया कि इन मॉडल दस्तावेजों में उच्च-जोखिम कैदियों, उग्रवादियों आदि को अन्य कैदियों से पृथक रखने के लिए विशेष सुरक्षा वाले कारागारों की व्यवस्था की संस्तुति दी गई है। पूर्व में जारी की गई सलाहों को दोहराते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अपेक्षा जताई है कि वे कठोर प्रवृत्ति के बंदियों की पहचान, निगरानी और परामर्श की प्रभावी व्यवस्था करें। गृह मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया है कि जो बंदी उग्र विचारधाराओं का प्रचार कर अन्य कैदियों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें सामान्य कैदियों से अलग रखा जाए। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हाई सिक्योरिटी प्रिजन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने पर विचार करना चाहिए ताकि आतंकवादियों व कट्टरपंथियों को अलग रखकर उनके प्रभाव को सीमित किया जा सके। परामर्श में कहा गया है कि इन बंदियों पर निगरानी उपकरणों और खुफिया तंत्र की सहायता से कड़ी निगरानी की जाए और भीतर चल रहे किसी भी उग्रवादी नेटवर्क की पहचान कर उसे समय रहते खत्म किया जाए। मोदी सरकार का यह भी मानना है कि बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों में जोड़कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। साथ ही, परिवार से निरंतर संपर्क बनाए रखने की सुविधा से उनकी भावनात्मक स्थिरता को भी बल मिलेगा, जिससे पुनः समाज में सफल पुनर्वास संभव हो सकेगा। बहरहाल, कैदियों के सुधार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम समयानुकूल और आवश्यक है। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन दिशा-निर्देशों को गंभीरता से लागू कर कारागारों को केवल सजा के केंद्र न बनाकर, सुधार और पुनर्वास के स्थलों में रूपांतरित करें।

दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी: एक महिला और बच्ची की हत्या, युवती का दोस्त मौके से फरार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन थाना इलाके में दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 22 साल की युवती और उसकी सहेली की बेटी की घर में ही हत्या कर दी गई है। आसपास के लोगों को जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पर मौजूद है। युवती का दोस्त मौके से फरार बताया जा रहा है। इस पर हत्या का शक जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श नगर इलाके में सोमवार रात तीन हमलावरों ने 17 साल के नाबालिग को गोली मार दी। नाबालिग की पहचान एमसीडी कालोनी निवासी आर्यन के रूप में हुई है। उसे दो गोली लगी है और उसका सिविल लाइन्स स्थित ट्रौमा सेंटर में इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश में गोली मारने की बात सामने आई है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि सोमवार रात 10.14 बजे आदर्श नगर थाना पुलिस को सिविल लाइन्स स्थित ट्रौमा सेंटर से एक नाबालिग को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। अस्पताल पहुंची पुलिस को पता चला कि 17 साल के आर्यन को दो गोली मारी गई है। अस्पताल में मौजूद उसकी मां नीतू ने बताया कि वह एमसीडी कॉलोनी में रहते हैं। रात में वह अपने बेटे आर्यन, परिचित रंजीता और निखिल के साथ एमसीडी कॉलोनी के मुख्य गेट फुट ओवर ब्रिज के पास फुटपाथ पर खड़ी थीं। सभी घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जहांगीरपुरी के रहने वाले तीन लड़के लड्डू, शमशेर और शानू वहां आए और ताबड़तोड़ गोली चला दी। आर्यन को दो गोली लगी। वह तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। आर्यन की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है।

अब दिल्ली में और सस्ती बिजली: बिना खर्च किए छत पर लगेगा सोलर प्लांट, सीएम रेखा ने की शुरुआत

नई दिल्ली। दिल्ली वाले केवल अपनी छत उपलब्ध करवाकर सौर ऊर्जा की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए कोई अग्रिम लागत नहीं लगेगी और कोई पूंजी निवेश नहीं करनी होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसकी मदद से दिल्लीवालों को सस्ती बिजली की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने आरईएससीओ/ यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के तहत पूरी राजधानी में रूफटॉप सोलर लगाने की व्यापक शुरुआत की है। यह पहल केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग संचालित कर रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर दिल्ली सरकार ने पहले से ही पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना-स्टेट टॉप-अप नामक योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना की मदद से दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के सौर ऊर्जा की सुविधा मिलेगी। इस मॉडल के तहत अब दिल्लीवाले अपने घरों या संस्थानों

पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन का कार्य उन डिवेलपर्स करेंगे। इन्हें संबंधित बिजली कंपनी नियुक्त करेगी। आरईएससीओ कंपनी उपभोक्ता की संपत्ति पर सौर पैनल स्थापित करती है और उसका प्रबंधन करती है। उपभोक्ता केवल उपयोग की गई बिजली के लिए भुगतान करता है। इस मॉडल में उपभोक्ता को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई अग्रिम निवेश नहीं करना पड़ता है। यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन एक मॉडल है जिसमें बिजली वितरण कंपनियां घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करती हैं।

तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों का लक्ष्य

इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने दावा किया कि हर छत एक बिजलीघर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे हर नागरिक स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का भागीदार बन सकेगा।

घरेलू व व्यावसायिक को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा घरेलू एवं गैर-घरेलू दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को संबंधित डिस्कॉम्स के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा की आपूर्ति डीईआरसी के तरफ से जारी मौजूदा सप्लाई कोड विनियमों के अंतर्गत संचालित होगी। इससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे। यह पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का प्रमुख हिस्सा है। सीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना पर 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी (10,000 रुपये प्रति किलोवाट) पहले ही मंजूर की जा चुकी है। इससे कुल उपलब्ध सब्सिडी 1.08 लाख रुपये हो गई है।

खरगे ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल, भाजपा की मांग- माफी मांगें

नई दिल्ली।

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भाजपा ने कहा कि यह कांग्रेस के आदिवासी विरोधी चेहरे को दिखाता है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि %उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया। सभी मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहा है। आप राष्ट्रपति को बिना किसी सम्मान के मुर्मा जी कहकर संबोधित करते हैं और फिर अंत में उन्हें भूमाफिया बताते हैं। पूरा देश जानता है कि अगर देश में कोई भूमाफिया है तो वह फर्जी गांधी परिवार है। गौरव भाटिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मुर्मा जी बुलाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति जी राम नाथ कोविंद जी को कोविड बुलाते हैं। खरगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भू-माफिया बताते हैं, कहते हैं, ये हमारी जमीन और जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति बनी हैं। राहुल गांधी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि उदित राज कहते हैं कि किसी देश को द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति नहीं मिलनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित करते हैं।

यह एक आदिवासी महिला के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिर्फ फर्जी गांधी परिवार के सदस्य ही देश में संवैधानिक पदों पर बैठ सकते हैं। अजय कुमार कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुरी मानसिकता को दर्शाती हैं। आज मल्लिकार्जुन खरगे का आपत्तिजनक बयान सबूत है कि उनकी कोई जुबान नहीं फिसली है। यह जानबूझकर किया गया। हम मल्लिकार्जुन खरगे से मांग करते हैं कि वे अपने बयान पर माफी मांगें।

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई सुनवाई, एएसजी ने दी दलीलें, 12 जुलाई मिली अगली तारीख

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की आंशिक दलीलें सुनने के बाद केस की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख नियत की है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए यंग इंडियन कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि मामले में ऋण की अदायगी, उस पर लगाए गए ब्याज और अन्य से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी की तरफ से दबा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ईडी की शिकायत बेतुकी बातों से भरी हुई थी और इसमें स्वाभाविक रूप से असंभव आरोप हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को आरोपों की सत्यता की जांच करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक थी, लेकिन जांच एजेंसी ने सतही जांच भी नहीं की। यह भी तर्क दिया कि मामले में शिकायत किसी सरकारी कर्मचारी ने नहीं बल्कि एक निजी नागरिक ने की है। मामले में शिकायतकर्ता व पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल उठाते हुए वकील ने कहा कि स्वामी दो हजार करोड़ रुपये के आंकड़े पर कैसे पहुंचे उन्होंने तर्क दिया कि आयकर विभाग का कहना है कि 90 करोड़ रुपये का ऋण एक फर्जी लेनदेन था। उन्होंने कहा कि पैसा कभी गया नहीं, लेकिन यही मामले का आधार बन जाता है। अगर सरकार के दो अंग अलग-अलग रुख अपना रहे हैं, तो अपराध कैसे संभव है वहीं, दूसरी तरफ मामले में आरोपी अन्य कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत को बताया कि ईडी ने मामले में गलत तरीके से कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने स्वामी की तरफ से मामले में मूल शिकायत की पंजीकृत प्रति प्राप्त किए बिना ईसीआईआर की।

बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश! संजय सिंह ने बीजेपी पर लगा दिए बड़े आरोप

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है. इस प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि यह नागरिकता पर सवाल उठाने जैसी प्रक्रिया है. एएनआई को दिए बयान में संजय सिंह ने कहा, एक मतदाता बनने के लिए जो आवश्यक प्रमाण होते हैं, उन्हें नहीं मानकर एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है. यह बिल्कुल ठीक नहीं है. संजय सिंह ने विशेष रूप से बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की गहरी साजिश है ताकि प्रवासी बिहारी वोट न दे सकें. उन्होंने कहा, बीजेपी को पता है कि जहां उनकी सरकार है, वहां बिहारी लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा है. जैसे दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के घर तोड़े गए... अब यदि वे वोट देंगे तो भाजपा के खिलाफ देंगे. इसलिए ऐसे लोगों को मतदान से वंचित करने की कोशिश की जा रही है. चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह पुनरीक्षण अभियान मुख्य रूप से दोहराए गए या फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए किया जा रहा है, खासकर वे जो एक ही समय पर दो पते स्थायी और वर्तमान पर दर्ज हैं. आयोग का कहना है कि केवल वे नागरिक जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें ही उस क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पड़ी- बच्चों की सुरक्षा पारिवारिक नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 साल के बच्चे के साथ कथित क्रूरता करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराध समाज की सामूहिक चेतना को प्रभावित करते हैं ,और इन्हें केवल निजी विवाद मानकर नहीं मिटाया जा सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक यह पूरा मामला जून 2023 का है. जब एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे के साथ उसके पड़ोसियों अमित और उसकी पत्नी ने मारपीट की और उसे बिजली के झटके तक दिए. इस मामले में दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. वहीं इस मामले में बाद में पीड़ित बच्चे की मां और आरोपी पक्ष के बीच समझौता हो गया था.

जिसको मुख्य आधार बनाकर आरोपी पक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी. वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित की मां ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बिना किसी दबाव और जोर जबदस्ती के यह समझौता किया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में साफ किया कि इस तरह के गंभीर आरोपों को केवल आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य सिर्फ पीड़ित को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा और जनहित से जुड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर को इस स्तर पर रद्द करना आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमजोर करेगा और एक गंभीर उदाहरण पेश करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़ित बच्चे के बयान को भी इस मामले में महत्वपूर्ण बताया, जिनमे उसने घटना का पूरा विवरण दिया था. हाईकोर्ट ने कहा जब बच्चा मात्र 7 साल का था तो उस पर इस तरह की हिंसा और मनोवैज्ञानिक आघात को हल्के में नहीं लिया जा सकता. भले ही झटका देने के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु टॉर्च ही क्यों ना रही हो. अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता, पीड़ित की उम्र और कानून उसके स्वाभाविक रास्ते पर चलने देने की आवश्यकता को देखते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं कर सकती है

एमबीबीएस में प्रवेश रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाए छात्र

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा के एक मेडिकल कॉलेज में बिना पूर्व सूचना के एमबीबीएस छात्र का प्रवेश रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की अवकाश कार्य दिवस (पीडब्ल्यूडी) पीठ ने छात्र के वकील हर्षित अग्रवाल से कहा कि वह अपनी शिकायत लेकर उच्च न्यायालय जाए। पीठ ने कहा कि याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है। छात्र के वकील हर्षित अग्रवाल ने 2024-2029 शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि उनका प्रवेश कथित तौर पर बिना किसी नोटिस या सुनवाई के किया गया। यह अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। याचिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता तय करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में अनुशासनात्मक मामलों में एक समान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की भी मांग की गई। पीठ ने अग्रवाल के उच्च न्यायालय न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के निर्णय पर सवाल उठाया। इस पर वकील ने एक पुराने मामले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने एक अन्य एमबीबीएस छात्र से जुड़ी इसी तरह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। वकील ने पीठ को संबंधित स्थानांतरण याचिका के बारे में भी बताया, जिस पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस पर न्यायमूर्ति बिंदल ने कहा कि हम यहां सीधे रिट याचिका पर विचार नहीं करने जा रहे हैं। इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने के लिए पीठ से अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। केंद्र के अलावा वकील अग्रवाल ने याचिका में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, चिकित्सा परामर्श समिति, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, सीबीआई और ओडिशा के बलांगीर स्थित भीम भोई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को भी पक्ष बनाया था।

जेएनयू में 11 दिन से जारी भूख हड़ताल, प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ छात्रों का उग्र विरोध, तेज हुआ आंदोलन

नई दिल्ली। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रसंघ (जेएनएसयू) द्वारा शुरू की गई है. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अपने 11वें दिन में पहुंच गई है. जेएनयूएसयू अध्यक्ष नितीश कुमार, काउंसलर अंतरिक्ष, और कार्यकर्ता लोनी, मणिकांत और शौर्य भूख हड़ताल पर बैठे है. उनकी मांगों में एकेडमिक एक्सटेंशन वाले पीएचडी छात्रों को हॉस्टल से बेदखल करने का निर्णय वापस लेना, जेएनयूईई की बहाली, MCM छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी और छात्र कार्यकर्ताओं पर लगाए गए अनुशासनात्मक दंडों को रद्द करना शामिल है. कल छात्रसंघ के आह्वान पर 236 छात्रों ने एकदिवसीय सामूहिक रिले भूख हड़ताल में हिस्सा लिया. इस आंदोलन को छात्रों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिसमें पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष धनंजय और ऐशे, साथ ही पूर्व उपाध्यक्ष अविजीत भी एक दिन की भूख हड़ताल में शामिल हुए. इस व्यापक समर्थन ने आंदोलन को और तेज कर दिया है. छात्रसंघ का कहना है कि पीएचडी के अंतिम चरण में पहुंचे छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहना अमानवीय है. अध्यक्ष नितीश कुमार ने कहा, यूजीसी की गाइडलाइंस के

तहत मिला एकेडमिक एक्सटेंशन तब तक बेमानी है, जब तक हॉस्टल में रहने की सुविधा नहीं मिलती. अधिकतर छात्रों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है. ऐसे में हॉस्टल से बेदखली उनके शोधकार्य को बाधित करेगी. जेएनयूएसयू ने यूजीसी-नेट आधारित प्रवेश प्रणाली को भी कठघरे में खड़ा किया है. उपाध्यक्ष मनीषा ने कहा, एनटीए परीक्षाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और समय पर आयोजित करने में विफल रहा है. जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अपनी प्रवेश परीक्षाएं खुद आयोजित करते हैं, तो जेएनयू क्यों नहीं उनका कहना है कि जेएनयूईई की वापसी से वंचित तबके के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश सुगम होगा. छात्रसंघ महासचिव मुंतहा ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, हड़ताल पर बैठे सभी छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है, वजन कम हुआ है और शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. इसके बावजूद प्रशासन ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और केवल दो खोखली अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं. दिल्ली के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के काउंसलर राजत और भाषा अध्ययन संकाय के छात्र ब्रेयस भी अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल हो चुके हैं. साथ ही स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के काउंसलर अभिषेक 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन का दायरा अब पूरे कैंपस में फैल चुका है. जेएनयूएसयू का कहना है कि जब तक प्रशासन इन चार प्रमुख मांगों, हॉस्टल बेदखली का निर्णय वापसी, जेएनयूईई की बहाली, एम्स स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी और दंडात्मक कार्रवाइयों की वापसी पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

दुर्लभ खनिजों पर दुनिया को एकजुट करने की पहल, मोदी ने दी चीन को कूटनीतिक चुनौती

नीरज कुमार दुबे ।

रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और उसे भू-राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने की जरूरत को जोरदार ढंग से उठाया। उनका यह भाषण ऐसे समय में आया है जब चीन विश्व की 90फीसदी से अधिक दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण क्षमता पर नियंत्रण रखता है और हाल ही में इन संसाधनों के निर्यात पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों से उसने वैश्विक चिंताओं को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह चेतावनी दी कि रणनीतिक संसाधनों का हथियारकरण वैश्विक असंतुलन को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी देश इन संसाधनों का अपने निजी स्वार्थ या दूसरों के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग न करे। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, परंतु संदर्भ और समय को देखते हुए यह टिप्पणी चीन के संदर्भ में एक अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि चीन को दुर्लभ खनिजों पर पकड़ स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे भविष्य के उद्योगों को नियंत्रित करने का माध्यम बनती जा रही है। हाल में चीन द्वारा इन खनिजों के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों ने अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों को आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को लेकर सचेत और चिंतित किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स मंच से अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और तकनीकी नवाचार के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ मृदा तत्व अनिवार्य हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला कुछ देशों के एकाधिकार में है, जो वैश्विक असंतुलन का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों से सामूहिक रूप से इस चुनौती से निपटने का आह्वान करते हुए कहा, हमें मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना होगा। देखा जाये तो यह संदेश केवल चीन की नीति के विरोध में नहीं था, बल्कि ब्रिक्स के भीतर सहयोग और विविधीकरण के नए अवसरों को तलाशने की दिशा में एक सक्रिय पहल भी थी। इसलिए मोदी ने एक ब्रिक्स क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सदस्य देश इन संसाधनों की खोज, निष्कर्षण और प्रसंस्करण में सहयोग कर सकें। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध और लचीला बनाया जा सके तथा ग्लोबल साउथ के देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा सके। भारत की यह पहल वैश्विक जलवायु लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर उद्योगों को बल देने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने केवल खनिजों तक सीमित न रहकर वैश्विक शासन प्रणाली में भी व्यापक बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाएं और विकासशील देशों को सशक्त आवाज दें। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), IMF, विश्व बैंक और WTO जैसे संस्थानों में सुधार की मांग भारत द्वारा लंबे समय से की जा रही है और यह भाषण उस नीति की निरंतरता है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत चीन की आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने के लिए पहले से ही कई उपायों पर काम कर रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर साझेदारी की जा रही है। खनिज सुरक्षा साझेदारी जैसे अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क में भागीदारी की गयी है। साथ ही घरेलू स्तर पर दुर्लभ खनिजों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखा जाये तो यह केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी निर्णायक कदम है। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह अमेरिका में संपन्न क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाने के उद्देश्य से 'क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव' की शुरुआत करने पर भी सहमति बनी है। यह कदम आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो चीन द्वारा इस क्षेत्र में मूल्य हेरफेर समेत अन्य दबावयुक्त रणनीतियों की चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स मंच से दिया गया संदेश इस बात का प्रमाण है कि भारत अब भविष्य की सामरिक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहना चाहता है, वह केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि संचालक और नीति-निर्माता के रूप में उभर रहा है। चीन के खनिज प्रभुत्व के विरुद्ध सामूहिक वैश्विक सोच को आकार देने के लिए प्रधानमंत्री का यह भाषण एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। हम आपको यह भी बता दें कि भारत अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा।

प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कहा है कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मानवता सर्वप्रथम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हमने अपनी अध्यक्षता के दौरान जी-20 को व्यापकता दी, एजेंडे में 'ग्लोबल साउथ' के मुद्दों को प्राथमिकता दी, उसी प्रकार ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस मंच को जन-केंद्रित और मानवता सर्वप्रथम की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, हम ब्रिक्स को एक नये रूप में परिभाषित करने के लिए काम करेंगे। ब्रिक्स का अर्थ होगा- सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलेपन तथा नवाचार का निर्माण करना। इसके अलावा, ब्रिक्स बैठक के इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार, यह बातचीत सीमित समय की थी परन्तु रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट कहना है कि भारत-चीन संबंधों का सामान्यीकरण LAC (Line of Actual Control) पर शांति और यथास्थिति की बहाली पर निर्भर करता है। इसके अलावा, हाल में कई स्तरों की वार्ताओं के दौरान भारत ने चीन के साथ व्यापार घाटे का मुद्दा भी उठाया और बाजार तक न्यायसंगत पहुंच की बात की। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं।

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद, जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा होगी। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री 14 और 15 जुलाई को आयोजित होने वाले एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए तियानजिन जाने से पहले अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता करने को लेकर बीजिंग की यात्रा करेंगे। जयशंकर की यह यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीनी शहर चिंगदाओ की यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद हो रही है। हम आपको बता दें कि चीन एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है और वह समूह की बैठकों की मेजबानी कर रहा है। बहरहाल, देखा जाये तो भारत की नीति अब विरोध के साथ संवाद वाली प्रतीत हो रही है- अर्थात जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रतिरोध और जहाँ संभव हो वहाँ सहयोग। यह संतुलन भारत की स्वायत्त रणनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। कुल मिलाकर देखें तो ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की दमदार उपस्थिति न केवल भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों की अभिव्यक्ति थी, बल्कि यह भी संकेत थी कि भारत अब क्रिटिकल मिनरल्स जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने को तैयार है। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में संयम और स्पष्टता दोनों का प्रदर्शन करके भारत ने यह भी सिद्ध किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना संवाद की नीति पर कायम है। आने वाले समय में यह संतुलन भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में और अधिक सशक्त करेगा।

मतदाता सूची पर बवाल !

बिहार में मतदाता सूची को लेकर आम मतदाताओं में जिस प्रकार भ्रम का वातावरण बना हुआ और विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची पुनरीक्षण को जिस प्रकार से मुद्दा बना रही हैं उसे देखते हुए चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वह सीधे मतदाताओं को यकीन दिलाये कि किसी एक भी वैध मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जायेगा और उसके वोट के अधिकार का पूरी तरह संरक्षण किया जायेगा। चुनाव आयोग ने विगत 24 जून को सूचना जारी कर कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। केवल आधार कार्ड होने से किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं जोड़ा जायेगा। चुनाव आयोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान सीधे आधार कार्ड से मतदाता सूची को संलग्न करने का अभियान चलाया गया था। मगर इस पर भी कुछ विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया था। दरअसल चुनाव आयोग सीधे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है और बीच में कहीं कोई सरकार नहीं आती। चुनाव आयोग सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपने दायित्व का निर्वाह करता है। वैध मतदाता को पंजीकृत करना उसका कर्तव्य होता है। यह भी तथ्य है कि केवल भारत का नागरिक ही मतदाता बन सकता है और इस क्रम में एक भी भारतीय नागरिक छूटना नहीं चाहिए। जहां तक आधार कार्ड का सम्बन्ध है तो इस पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि यह केवल आवास की पहचान है नागरिकता की नहीं। अर्थात आधार कार्ड भारत में रहने वाले की पहचान करता है न कि उसकी नागरिकता की। मगर दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि किसी भी सरकारी सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को ही जरूरी बना दिया गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की जिससे यह पता चल सके कि मतदाता वास्तव में भारत का नागरिक है और सूची में जुड़ने योग्य है। ये 11 दस्तावेज इस प्रकार हैं- 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पेंशन कार्ड या पहचान पत्र, 2.सरकार या स्थानीय निकाय प्रशासन अथवा बैंक, डाकखाने या जीवन निगम द्वारा 1987 से पूर्व उसके नाम जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या अन्य कागज, 3. किसी मान्य प्रमाणित संस्था द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र, 4. पासपोर्ट, 5. हाई स्कूल का प्रमाणपत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख होता है, 6. किसी भी मान्य प्रमाणित राज्य संस्था द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी होने का प्रमाणपत्र, 7. वन विभाग द्वारा वनों पर अधिकार होने का जारी प्रमाणपत्र, 8. पिछड़े वर्ग का होने अथवा आदिवासी या अनुसूचित वर्ग से होने का सर्टिफिकेट। बिहार में 2022 में जाति सर्वेक्षण हुआ था जिसमें बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ सात हजार पाई गई थी। इसमें सामान्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या 27 प्रतिशत थी जबकि अत्यन्त पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत व आदिवासी वर्ग के केवल 1.6 प्रतिशत थे। 9 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में मतदाता का नाम (बिहार पर यह लागू नहीं होता है क्योंकि वहां यह रजिस्टर बना ही नहीं है)। 10. राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय परिवार रजिस्टर में नाम। यह रजिस्टर प्रायः स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका व ग्राम पंचायत आदि बनाते हैं, 11. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय प्रशासन द्वारा जारी किया गया कोई भूमि आवंटन प्रमाणपत्र। इस प्रकार इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना चुनाव आयोग ने मतदाता बनने के लिए जरूरी बना दिया है। इसे लेकर ही बिहार में भारी कोहराम मचा हुआ है और आम जनता में भ्रम का वातावरण फैला हुआ है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दल 9 जुलाई को बिहार बन्द भी आहूत कर रहे हैं। इससे यह खतरा पैदा हो रहा है कि राज्य में आम जनता व चुनाव आयोग सीधे आमने-सामने आकर खड़े हो गये हैं। यह स्थिति किसी भी रूप में सही नहीं कही जा सकती क्योंकि चुनाव आयोग मतदाता सूची का संरक्षक होता है जिसके आधार पर अधिक से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। मगर मतदाताओं को यदि यह लगने लगे कि चुनाव आयोग उन्हें मतदाता बनने से महरूम कर रहा है तो लोकतन्त्र के लिए ये हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते लेकिन इस बीच बिहार के चुनाव आयुक्त ने एक अखबार में विज्ञापन जारी करके कहा है कि मतदाता अपना पंजीकरण बिना किसी एक दस्तावेज के भी करा सकते हैं जबकि दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और 24 जून 2025 के दिशा-निर्देश वैध रहेंगे। इससे स्थिति और उलझ गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह 30 सितम्बर को नई पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी कर देगा और इससे पहले 1 सितम्बर तक मतदाता 11 में से कोई एक दस्तावेज जमा करा सकते हैं और अपना फार्म भर कर इसे 25 जुलाई तक स्थानीय पंजीयक गणक को दे सकते हैं। भारत में जाली मतदाता होने का आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लगाया था और कहा था कि मतदाता सूची में लाखों नये मतदाताओं के नाम फर्जी तौर पर जोड़े गये थे।

चुनाव आयोग ने उसके जवाब में ही यह कदम उठाया लगता है मगर यह काम जितनी जल्दबाजी में किया गया है उससे इस प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अतः चुनाव आयोग को इस सन्दर्भ में अपनी विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगले वर्ष प. बंगाल व तमिलनाडु में भी विधानसभा

सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करनी होगी

पूरी दुनिया में सूचना और संचार क्रांति की अंधी दौड़ मची है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका इंटरनेट निभा रहा है। आज जिनके पास भी इंटरनेट है उनका एक अहम समय इस पर ही व्यतीत होता है, खासकर सोशल मीडिया पर। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिये सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिये हैं, डेढ़ दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल, इस मंच के जरिये समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिये चर्चा में रहता है। दरअसल, सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना के खिलाफ इंटरनेट (सोशल) मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर, ऐसी सामग्री पोस्ट करना जो लोगों के बीच वैमनस्य और घृणा पैदा करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना कुछ लोगों के समूहों के बीच फैशन'' बन गया है। एक अन्य मामले में बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी की जमानत खारिज करते हुए डिजिटल मीडिया के अपराधीकरण पर चिंता जाहिर की है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने व्हाट्सएप पर एक महिला की अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने के आरोपी रामदेव की जमानत अर्जी खारिज की। आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी जमकर किया जा रहा है मगर इसका इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वह वाकई चिंता का विषय है। राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ उनके समर्थक भी अवसर शालीनता की सारी हदें पार कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के समय चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वे ऐसी सामग्री प्रकाशित न करें जो झूठी, भ्रामक या अपमानजनक हो, खासकर महिलाओं के प्रति। अभियान सामग्री में बच्चों का उपयोग और हिंसा या जानवरों को नुकसान पहुंचाने का चित्रण भी निषिद्ध है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में सख्त टिप्पणियां कर चुका है। साल 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी-अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध-प्रदर्शन का दौर प्रारंभ हो गया था। यह हिंसक विरोध-प्रदर्शन स्वतः परंतु सोशल मीडिया द्वारा विनियोजित था। इससे पूर्व अरब की सड़कों पर शुरू हुए प्रदर्शनों (जिसने कई तानाशाहों की सत्ता को चुनौती दी) में भी सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया

सम्पादकीय...

नशे में डुबाने की खतरनाक साजिश

कनाडा के विभिन्न इलाकों में घूमते हुए मैं आश्चर्यचकित था कि यह देश किस तरह नशे के सौदागरों की गिरफ्त में फंस चुका है। गांजा, अफीम और कोकीन से लेकर हेरोइन तक बाजार में बड़ी सहजता से मिल रहा है, आप वहां से गुजरेंगे तो नशे की दुर्गंध से परेशान हो जाएंगे। यहां तक कि घर विहीन लोगों को शेल्टर होम में ले जाया जाता है तो वहां भी उन्हें ड्रग्स उपलब्ध होता है। नशे की सामग्री का कोड नेम ग्रास, व्हीट और न जाने क्या-क्या है। वैसे यूरोप के कई शहरों में ड्रग्स के मेनू कार्ड होते हैं, जो चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। वहां के हालात देख कर मुझे देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गाना याद आ रहा था-दम मारो दम। कनाडा और उन यूरोपीय देशों की इस दुर्दशा को लेकर मेरे मन में मंथन चल ही रहा था कि मैंने अपने अखबार के इंटरनेट संस्करण में खबर पढ़ी कि पंजाब और राजस्थान में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है और ड्रग्स की तस्करी करने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सरगना उनवीर सिंह पाकिस्तान में बैठा है तो दूसरा सरगना जोबन कालेर कनाडा में है। ये दोनों तस्कर भारत में गुरसाहिब सिंह नाम के स्थानीय ड्रग्स तस्कर के माध्यम से भारत में ड्रग्स पहुंचा रहे थे। गुरसाहिब सिंह पंजाब की एक जेल में बंद है लेकिन मोबाइल के माध्यम से वह अपने भतीजे जशनप्रीत सिंह और साथी गगनदीप सिंह को निर्देश देता था और वे दोनों गिरोह को चला रहे थे। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ और निश्चय ही आपके मन में यही सवाल उठा होगा कि गुरसाहिब सिंह के पास जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा? निश्चित रूप से जेल के पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे। बिना मिलीभगत के यह संभव ही नहीं है। ड्रग्स की तस्करी में इतना पैसा है कि किसी अधिकारी की झोली में सौ-पचास करोड़ डालने में तस्कर क्या हिचकेंगे? नशे के कारोबार को लेकर मैंने अपने आलेखों में कई बार आगाह किया है कि यह भारत के खिलाफ एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ड्रग्स कारोबार के रिश्ते आतंकवाद से भी जुड़े हुए हैं, महान विचारक चाणक्य ने कहा था कि जो लोग नशा करते हैं, वो अपना भविष्य तो समाप्त करते ही हैं, समाज के लिए भी वे घातक साबित होते हैं। हमारे दुश्मन मुल्क की कोशिश है कि हमारे रचनात्मक युवा नशे के शिकार हो जाएं। यही कारण है कि हर तरफ से भारत में ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, पिछले साल दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलोग्राम कोकीन व 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना तथा दिल्ली के ही रमेश नगर से 208 किलो कोकीन बरामद की गई। उस मामले को लेकर थोड़ा हल्ला मचा क्योंकि उसमें एक राजनेता का नाम आ गया था। इधर गुजरात के अंकलेश्वर में सात हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई थी, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके झाबुआ में भी 168 करोड़ की ड्रग्स मिली थी। थोड़ा पीछे लौटें तो 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 21 हजार करोड़ रुपए मूल्य की 3 हजार किलो हेरोइन जब्त की गई थी, जब्ती की ऐसी लंबी सूची है लेकिन यह समंदर की एक बूंद जैसा है क्योंकि दुनिया में ड्रग्स माफिया समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और भारत में ड्रग्स का कारोबार लाखों-लाख करोड़ का है। पहले केवल फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बाप की बिगड़ी औलादों की रेव पार्टी का ही जिक्र होता था लेकिन अब ड्रग्स का कारोबार हर जगह फैल चुका है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांव, कस्बे भी नशे का शिकार हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नशे के सौदागर सातवीं-आठवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ये बच्चे ड्रग्स लेते भी हैं और पहुंचाने का काम भी करते हैं। जब नशे के शिकार होते हैं तो स्वाभाविक रूप से इनसे विभिन्न तरह के अपराध भी करवा लिए जाते हैं। चूंकि वे वयस्क नहीं होते हैं इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती। गोवा में नशे के कारोबार के बारे में तो लोगों को पता ही है। पूर्वोत्तर के राज्यों को भी नशे ने खोखला कर दिया है। पंजाब की स्थिति को लेकर तो उड़ता पंजाब नाम की एक फिल्म भी बनी थी, अब जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जल्दी ही उड़ता बिहार फिल्म भी बनानी पड़ेगी। अब सवाल है कि ड्रग्स भारत में आ कैसे रहा है? भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में चोरी-छुपे गांजे की खेती होती होगी लेकिन अफीम, कोकीन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स तो बाहर से ही आ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफीम की खेती और उसे प्रोसेस करने का काम होता है। पाकिस्तानी तस्कर और आतंकी संगठन ड्रग्स को राजस्थान, पंजाब और गुजरात के इलाके से भारत में भेजते हैं। राजस्थान और पंजाब सीमा पर ड्रोन से लगातार ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी ड्रोन पकड़ भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। इन राज्यों में ड्रग्स भेजने में पाकिस्तानी हैंडलर्स प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कनाडा में बैठे हैंडलर्स ने पंजाब में पहले से नेटवर्क खड़ा कर रखा है जो मददगार होते हैं, ड्रग्स का एक प्रमुख मार्ग नेपाल सीमा भी है जिस पर चीनी हैंडलर्स का होल्ड है और म्यांमार में सक्रिय उग्रवादी संगठन भी ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं। तस्करों को इस बात का फायदा मिलता है कि बॉर्डर के दोनों ओर एक जैसी शक्ल वाले लोग रहते हैं। ऐसे में तस्करों को पहचानने का तरीका यही है कि हमारे पास बेहतरीन खुफिया तंत्र हो, अत्यंत सजग सुरक्षाकर्मी हों और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बॉर्डर से ड्रग्स तस्करी रोकने का पुख्ता मैकेनिज्म अभी तक हम विकसित नहीं कर पाए हैं, सिस्टम में इतने छेद हैं कि कितनी जगह पैच चिपकाएंगे? इसलिए शीर्ष पर बैठे विभाग प्रमुखों के खिलाफ भी जब कार्रवाई होगी तभी सिस्टम सुधरेगा। चलिए, मैंने तो ये सारी बातें लिख दीं लेकिन क्या हमारे प्रबुद्ध सांसद इस खतरनाक साजिश को लेकर संसद में चर्चा करेंगे?

भारतीय पीएम का आगाज़ ग्लोबल साउथ दोहरे मापदंडों का हो रहा है शिकार

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ परंतु विशेष रूप से यूरोप व विकसित देशों को ब्रिक्स देशों के अति महत्वपूर्ण व संभाव्य रुतबे का जरूर एहसास होगा, क्योंकि यह पहले 7 देशों का परिवार था,जो अभी बढ़कर 11 हो चुके हैं और भविष्य में 30 तक जाने की संभावना है,इन मजबूत देशों को किसी वैश्विक निर्णायक मोड टेबल पर स्थान नहीं दिया गया है,जबकि दुनियाँ को 42 पर्सेंट आबादी से अधिक, जीडीपी में 23 परसेंट, व्यय में 17 परसेंट, वैश्विक विकास, व्यापार व निवेश में बहुत बड़ा योगदान है, वैश्विक गरीबी से लड़ने में महत्वपूर्ण सहयोग व तेल गैस प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर 11 देशों का व्यापार अमेरिकी डॉलर से होता है जो एक मुद्दा बना कि ब्रिक्स देशों को अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में लाया जाएगा,जिसपर फरवरी 2025 में ट्रंप ने कहा था कि अगर डॉलर से छेड़छाड़ की गई तो 100 से 500 परसेंट तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि इस बार ब्राजील में हो रहे 17 वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कुछ फीका सा लग रहा है, क्योंकि इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व ईरानी राष्ट्रपति हाजिर नहीं हुए हैं, जो शायद ब्रिक्स के जीवनकाल में पहली बार हो रहा है, कई और नेताओं के न आने के कारण ब्राजील और लेटिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में रियो डी जेनेरियो में हो रही इस बैठक को कम भागीदारी वाली% और यहां तक कि %खाली% बताया जा रहा है,ब्राजीलमीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिक्स के एक और अहम नए सदस्य मिस्र के राष्ट्रपति भी बैठक में मौजूद नहीं होंगे ब्रिक्स के मुख्य सदस्य देशों में से भारत के पीएम और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ नए सदस्य इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए हैं,हालांकि, ब्राजील और अन्य क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इतने नेताओं के न आने से वामपंथी मेजबान लूला डि सिल्वा की खुद को अंतरराष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश प्रभावित हो सकती है।दरअसल, ब्रिक्स देशों के बीच खुद भी मतभेद हैं, जहां चीन और रूस अमेरिका विरोधी सख्त रुख अपनाते हैं, वहीं भारत और ब्राजील संतुलित रुख के पक्षधर हैं, इस साल सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति की कोशिश है कि एआई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहकर सम्मेलन को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए, ट्रंप की अमेरिका में सत्ता में वापसी के बाद ब्राजील नहीं चाहता कि वह किसी भी तरह के अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना बने।ब्रिक्स नेताओं,ने यह चेतावनी भी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अंधाधुंध आयात शुल्क से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

अंतिम शिखर सम्मेलन के वक्तव्य के अनुसार, ब्रिक्स नेताओं ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की,तथा चेतावनी दी कि ये अवैध और मनमाने हैं।चूंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन व शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी व भारतीय पीएम का आगाज़, ग्लोबल साउथ दोहरे मापदंड का हो रहा है शिकार, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे ग्लोबल साउथ को वैश्विक संस्थाओं को निर्णय टेबल पर प्रतिनिधित्व नहीं देना जैसे मोबाइल में सिम तो है, पर नेटवर्क नहीं सटीक कटाक्ष है। साथियों बातअगर हम एक ऐसे ब्रिक्स की परिकल्पना करने की करें जो कुछ परिणाम देगा,तो उनमें से, जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण,कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वित्तपोषण और विनियमन पर एक समर्पित घोषणा, और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों पर साझेदारी,वे बीमारियाँ जिन्हें हम गरीबी की स्थिति से जोड़ते हैं। पहले सत्र के अलावा, रियो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सभी सत्र भागीदार देशों और आमंत्रित देशों के लिए खुले रहेंगे। यह मानवता की बड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मंच में पारदर्शिता और समावेशिता का एक प्रयास है। एक स्पष्ट संकेत यह है कि 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। यह बहुत कुछ कहता है।अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ता है तो वे उसके खिलाफ 100-500 पैर्सेंट टैरिफ लगा देंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव या चर्चा सम्मेलन में नहीं होने की संभावना है। साथियों बात अगर हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 मेंरविवार 6 जुलाई 2025 को देर शाम भारतीय पीएम के संबोधन की करें तो,उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार रहा है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों के वितरण की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। जलवायु वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को अवसर सिर्फ औपचारिक

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध केंद्र सरकार की नई पहल- मानस-1933 हेल्पलाइन नंबर शुरू

पानीपत। डीसी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि 'नशा मुक्त भारत 2047' अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नार्कोटिक्स तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक अहम कदम उठाया गया है। इस दिशा में गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन - मानस - 1933 की शुरुआत की गई है। यह हेल्पलाइन नंबर 24×7 सक्रिय रहेगा और नागरिकों को किसी भी समय नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की जानकारी साझा करने की सुविधा देगा। डीसी डॉ. वीरेन्द्र दहिया ने बताया कि विशेष बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे लोग बिना किसी डर या संकोच के नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से जुड़ी जानकारी साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल समाज में व्याप्त नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि इससे युवाओं को भी इस बुराई से बचाने में बल मिलेगा। केंद्र सरकार का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है और इस दिशा में जन-सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीसी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की नशीली दवाओं के व्यापार, तस्करी या दुरुपयोग की जानकारी हो, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1933 पर तुरंत सूचित करें।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन

पानीपत। डीसी डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगामी 31 जुलाई तक अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डीसी ने राष्ट्रीय एकीकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठनों से नामांकन के लिए आह्वान किया। सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार विशिष्ट और प्रेरणादायक व्यक्तियों को पहचान प्रदान करता है, ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही मजबूत और एकजुट भारत के महत्व पर बल दिया जा सके। सभी भारतीय नागरिक और संगठन इसके लिए पात्र हैं। नामांकन केवल आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल एनटीपीएस// अवार्ड्सडॉट नीऑवेबडॉटइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन विंडो 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक खुली रहेगी। नामांकन में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए।

फसल अवशेष प्रबन्धन के लिये अनुदान पर दिए जाएंगे कृषि उपकरण, 15 जुलाई तक करें आवेदन- उप निदेशक डॉ0 आत्मा राम

पानीपत। उप निदेशक डा0 आत्मा राम ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये फसल अवशेष प्रबन्धन की कड़ी में फसल अवशेष मशलाई चेन योजना के तहत आवेदन करने के लिये पोर्टल खोल दिया गया है। इसके लिये इच्छुक कोई भी बायोमास इंडस्ट्रीज, एफ0पी0ओ0, किसान समूह व व्यक्तिगत किसान ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना में कोई भी बायोमास इंडस्ट्रीज किसी भी एग्रीगेटर के साथ द्विपक्षीय समझौता सहित आवेदन कर सकती है। इसके लिये प्रोजेक्ट लागत का 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत एग्रीगेटर द्वारा तथा बाकी हिस्सा इंडस्ट्रीज द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई एफ0पी0ओ0 किसान समूह व व्यक्तिगत किसान यदि द्विपक्षीय के बिना आवेदन करता है तो प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत हिस्सा खुद ही वहन करना होगा व 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। सहायक कृषि अभियन्ता सुधीर कुमार ने बताया कि इस स्कीम में 3500 एमटी पैडी स्ट्रा पर योजना के लिये एक करोड़ प्रोजेक्टर लागत तथा 4500 एमटी पैडी स्ट्रा पर योजना के लिये 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट लागत रखी गई है। यह योजना पैडी मशलाई चेन के लिये 12 मशीने शामिल की गई है, जिसमें कटर / रोटरी स्लेशर, टेडर मशीन, रेकर, टैक्टर 90-110 एचपी स्ट्रा बेलर र (रेक्टअगुलर और राउंडबेलर), टैक्टर 50 एचपी0 (टेडर मशीन व रेकर के लिए), ट्राली (फ्लेट मिंगल, एक्सेल, स्थानीय निर्माता, स्वचालित बेल लोडिंग ट्राली), टेली हैंडलर, जमी मोटर, वाटर टैंक (5000 लीटर), आग बुझाने का यन्त्र, लाइटनिंग अरेस्टर मशीन शामिल की गई है।

अविश्वास प्रस्ताव के बाद जगतार सिंह व श्रीमती मीनू जाखल पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए पुनः मनोनीत

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने फतेहाबाद जिले की जाखल पंचायत समिति के शेष कार्यकाल अवधि के लिए श्री जगतार सिंह को अध्यक्ष व श्रीमती मीनू को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री जगतार सिंह, अध्यक्ष व श्रीमती मीनू, उपाध्यक्ष के विरुद्ध 3 जून, 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 24 जून को हुए चुनाव के उपरांत श्री जगतार सिंह और श्रीमती मीनू पुनः इन्हीं पदों पर निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों को अधिसूचित किया है।

सीआईएसएफ ने विश्व पुलिस व फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर बढ़ाया देश का गौरव

चंडीगढ़। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में 64 पद जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत इन खेलों में 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई, 2025 तक आयोजित विश्व पुलिस और फायर खेलों-2025 में सीआईएसएफ ने 64 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व पुलिस और फायर खेल एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जहाँ दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मी विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वर्ष 70 से अधिक देशों के 10 हजार से अधिक एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया। प्रवक्ता ने बताया कि सीआईएसएफ की टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और शानदार खेल भावना, शक्ति और टीम वर्क दिखाया। सीआईएसएफ निरंतर फिटनेस, अनुशासन और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में टीम का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे बल सदस्यों की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इन खेलों में हरियाणा के एथलीटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें हरियाणा के जींद जिले के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक, हैमर थ्रो में रजत पदक, डेकाथलॉन, ट्रिपल जंप व पोल वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर योगदान दिया। इसी प्रकार, कुश्ती में हरियाणा के सीआईएसएफ एथलीटों झज्जर के एएसआई/कार्यकारी सनी कुमार, हिसार के एचसी अभिमन्यु, सोनीपत के एचसी/जीडी अजय डागर, एचसी हरीश, एचसी मोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि एथलेटिक्स में हरियाणा के हिसार की एल/एएसआई रीनू ने 10 किमी क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक, हाफ मैराथन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है।

राज्य मंत्री राजेश नागर से मिले हरियाणा उचित मूल्य दुकान व्यापारी संघ के पदाधिकारी

चंडीगढ़। हरियाणा उचित मूल्य दुकान व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने आज हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री श्री राजेश नागर से आज चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और ज्ञापन पत्र सौंपा। इस अवसर पर डिपो धारकों ने राज्य मंत्री के समक्ष लंबे समय से लंबित अपनी समस्याएं रखी और उनका जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। पदाधिकारियों ने श्री नागर को धरातल की समस्याओं से अवगत करवाया। पदाधिकारियों ने मुद्दों की एक सूची भी राज्य मंत्री श्री नागर को सौंपी और कहा कि वे उनसे सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आचार्य भिक्षु स्वामी जी को दी श्रद्धांजलि, 300वीं जयंती समारोह में की शिकरत

भिक्षु स्वामी जी के अहिंसा और अनेकांतवाद के सिद्धांत आज की जरूरत- मुख्यमंत्री

महापुरुषों के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर करें नैतिक समाज का निर्माण

विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज होगा चरित्रवान

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें, तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। यदि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत, नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण सबसे पहली आवश्यकता है। महापुरुषों की प्रेरणा से ही हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंचासीन परम श्रद्धेय मुनिश्री विनय कुमार आलोक जी, मुनिश्री सुधाकर जी, मुनिश्री अभय कुमार आलोक जी, मुनिश्री नरेश जी, स्वामी सम्पूर्णानन्द ब्रह्मचारी जी महाराज सहित समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर तेरापंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है। संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है।

मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वे भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। तीर्थंकरों और मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं।

आचार्य भिक्षु स्वामी जी समाज-सुधारक और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं, बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्कसंगत दिशा दी। विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में जन्मे 'भीखण' का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत् 1817 में तेरापंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। एक आचार्य, एक विधान और एक विचार का सिद्धांत तेरापंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है।

भिक्षु स्वामी जी के विचार आज के युग में भी प्रासंगिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल मारपीट न करना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है।

युवा आत्मानुशासन और आदर्शों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी मानते थे कि जब व्यक्ति सुधरेगा, तब समाज और राष्ट्र भी अपने आप सुधर जाएगा। हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उनका जीवन निडरता, सच्चाई, संयम और देशसेवा की अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब समाज चरित्रवान, संयमी और नैतिक मूल्यों से युक्त हो। इस अवसर पर मुनि श्री विनय कुमार आलोक एवं मुनिश्री सुधाकर जी ने मुनि श्री भिक्षु जी महाराज के जीवन एवं तेरापंथ के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की शिक्षाओं पर बोलना आसान है, परंतु उन शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना कठिन कार्य है। हम सभी को उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तेरापंथ की मुख्य विशेषता एक गुरु, एक विधान है तथा पंथ के अनुयायी अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं।

न्यायिक सुधार मुहिम में अग्रणी बना हरियाणा, आपराधिक न्याय में रचा इतिहास

चंडीगढ़। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी को छह महीने से भी कम समय में सजा हो जाए, यह किसी ने सपने में भी न सोचा होगा। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, कई अन्य आपराधिक मुकदमे भी 20 दिनों से कम समय में पूरे हुए हैं। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित अपराध के मामलों में, कई जिलों में सजा दर 95 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा, चिन्हित अपराध पहल के जरिए, 1,683 जघन्य मामलों को सख्ती से फास्ट-ट्रैक किया गया है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई है। यह सब हरियाणा की त्वरित, कुशल और पारदर्शी न्याय दिलाने की क्षमता का जीता जागता सबूत है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रदर्शनी के छलिया दौरे के बाद आज मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत, हरियाणा ने केवल राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। समय और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रदेश के इस मॉडल की बड़े पैमाने पर सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि विशाल क्षमता निर्माण पहल हरियाणा के सुधारों की रीढ़ है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान न केवल कानूनी समझ बल्कि पीड़िता-संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया। राज्य पुलिस बलों के बीच कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से, 37,889 अधिकारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ई-समन और ई-साक्ष्य जैसे प्लेटफार्मों के सफल कार्यान्वयन के बल पर हरियाणा ने डिजिटल पुलिसिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब 91.37 फीसदी से अधिक समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि शत-प्रतिशत तलाशी और जब्ती डिजिटल तरीके से दर्ज की जाती है। उल्लेखनीय है कि 67.5 प्रतिशत गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं। इससे न केवल साक्ष्य संग्रह का मानकीकरण हो रहा है बल्कि जांच में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में पॉक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के माध्यम राज्य के लिंग-संवेदी न्याय के दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित हो रही है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. मिश्रा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, गवाहों की जांच अब पारंपरिक अदालतों से आगे बढ़ चुकी है। गवाहों की जांच अब 'निर्दिष्ट स्थानों' पर की जा सकती है। इन 'निर्दिष्ट स्थानों' में सरकारी कार्यालय, बैंक और सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य स्थान शामिल हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए 2,117 'निर्दिष्ट स्थान' बनाए गए हैं, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सभी जिलों में महिलाओं/कमजोर गवाहों के लिए विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम/सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य ने अपने फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है। हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक वैन और बड़े जिलों में दो वैन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, 68.70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरण खरीदे गए हैं। राज्य सरकार ने 208 नई फॉरेंसिक पदों को मंजूरी दी है। इसमें 186 पद भरे जा चुके हैं, जिससे सबूत जांच को और मजबूती मिली है। कवीफतो में ट्रैकिया और 'डाकसम्प्ट' (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मार्टम रिपोर्टिंग) जैसे प्लेटफॉर्म का सहज एकीकरण किया गया है। इसके माध्यम से पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच रिपोर्ट अब सात दिनों के भीतर डिजिटल रूप से दर्ज की जाती हैं, जिससे चार्जशीट दाखिल करने और केस के फैसले में तेजी आई है। क्राइम-ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हरियाणा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और चिन्हकोनो जैसे बायोमेट्रिक और डिजिटल पहचान उपकरणों का भी बखूबी लाभ उठा रहा है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि करनाल में "न्याय शक्ति" पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से न्यायिक पहुंच को आधुनिक बनाया गया है। वहाँ पर पाँच जिला न्यायालय अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल से सुसज्जित हैं। अब 50 फीसदी से अधिक पुलिसकर्मी और 70 फीसदी आरोपी न्यायिक कार्यवाही में वर्चुअली भाग ले रहे हैं। इससे आरोपियों को न्यायालय लाने-ले जाने से जुड़ी चुनौतियों में काफी हद तक कमी आई है। साथ ही, समय और सार्वजनिक संसाधनों की भी बचत हुई है।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसहभागिता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग गंभीर

राजनीतिक दलों से की विस्तृत चर्चा, बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान जारी

अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को होगी प्रकाशित

मतदाता फॉर्म भरने और दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। इसी क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बिहार में चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसकी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क दी जाएगी।

चरणबद्ध तरीके से चल रहा विशेष पुनरीक्षण अभियान-

1.55 लाख बूथ लेवल एजेंट्स निभा रहे सक्रिय भूमिका

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी से जनसहभागिता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। 25 जून से 3 जुलाई 2025 के बीच 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए नामांकन फॉर्म वितरित किए गए हैं। साथ ही, अतिरिक्त 20,603 BLOs की नियुक्ति की जा रही है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही प्रक्रिया

फॉर्म वेबसाइट और घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे

ECI की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। नामांकन फॉर्म 23 जून 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं और 24 जून की मतदाता सूची में दर्ज नामों के आधार पर घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।

कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु 4 लाख स्वयंसेवकों की तैनाती

दूसरे चरण में 25 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म

दूसरे चरण में, 25 जुलाई तक नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कार्य को सुगम बनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों, एनसीसी, एनएसएस, और अन्य संस्थाओं के 4 लाख स्वयंसेवकों को BLOs के साथ जोड़ा गया है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और गरीब वर्गों को सहायता मिल सके।

तृतीय चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फॉर्म अपलोडिंग

BLO App और ECINET के माध्यम से रोजाना अपलोड होगा डेटा

25 जून से 26 जुलाई के बीच BLOs द्वारा फॉर्म और दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें BLO App या ECINET प्लेटफॉर्म पर रोजाना अपलोड किया जाएगा। मतदाताओं को प्राप्ति रसीद भी प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा भी दी गई है।

1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित

फॉर्म-6 के माध्यम से दावे और आपत्तियों का मौका मिलेगा

चौथे चरण में, 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनके फॉर्म 25 जुलाई से पूर्व जमा हो चुके होंगे। बीएलए प्रतिदिन 10 फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

पांचवां चरण- 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्रक्रिया

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई सुनिश्चित

इस अवधि में नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका परीक्षण धारा 16 और 19 के अनुसार संबंधित अधिकारी करेंगे। किसी नाम को सूची से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी दावे और आपत्तियां प्रतिदिन क्षेत्र कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी और साप्ताहिक रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी।

हरित आईएमटी अभियान की ओर हरियाणा का बड़ा कदम- जुलाई-अगस्त में होगा व्यापक पौधारोपण अभियान

15 जुलाई को राज्यभर में एक साथ चलेगा मास पौधारोपण अभियान

चंडीगढ़।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कहा है कि जुलाई-अगस्त माह के दौरान KMP एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एवं सभी आईएमटीस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। विशेष रूप से आईएमटी मानेसर को हरित आईएमटी के रूप में विकसित करने के लिए एचएसआईआईडीसी को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री राव नरबीर सिंह वन महोत्सव-2025 को लेकर आयोजित विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी मास पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों व नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी सभी इंडस्ट्रियल एरिया और आईएमटीस में अधिक से अधिक छायादार पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन व बड़ जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रजातियों के परिपक्व पौधों को राज्य की नर्सरियों में 3-4 वर्षों तक तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में रोपा जा सके। आईएमटी मानेसर के सभी खुले स्थानों में बहुउद्देशीय पार्क, ओपन एयर थियेटर जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। हर सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और सड़कों के नाम उसी प्रजाति पर रखे जाएंगे। शहरी चौराहों पर पौधारोपण की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाएगी और वहां उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। पौधों की सिंचाई और संरक्षण हेतु सौर पंप लगाए जाने की योजना बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का वन महोत्सव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हरियाणा को हरियाली की ओर अग्रसर करने का सुनियोजित अभियान होगा। वन विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा, जबकि एचएसआईआईडीसी, उद्योग और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पौधों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा। इस बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य, दिव्य और यादगार साबित होगा: उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के मुकाबले 23, 24 और 25 जुलाई को शिवाजी स्टेडियम और आर्य पीजी कॉलेज में होंगे खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएगी बेहतरीन खेल किट

हर डेस्टिनेशन पर मौजूद रहेगी स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस

उपायुक्त ने एसडीएम को संभावित डेस्टिनेशन का दौरा करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के लिए ठहरने व भोजन की उचित व्यवस्था होनी

पानीपत।

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 को सफल एवं यादगार बनाने को लेकर उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने मंगलवार को जिला सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां सौंपी और आयोजन से संबंधी कमेटी का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने एसडीएम को संभावित डेस्टिनेशन का दौरा करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के लिए ठहरने व भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरते। इस राज्य राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में खो - खो और तलवार बाजी के रोचक मुकाबले होंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस महाकुंभ की तिथि में परिवर्तन किया गया है पहले ये आयोजन 11 जुलाई से 13 जुलाई तक होना थे लेकिन अब इनकी तिथि में परिवर्तन किया गया है अब यह आयोजन 23 जुलाई से 25 जुलाई को होगा। उपायुक्त ने बताया कि दो इवेंट के इस राज्य स्तरीय आयोजन में खो खो के मुकाबले शिवाजी स्टेडियम में व तलवारबाजी के मुकाबले आर्य पीजी महाविद्यालय में होंगे। उपायुक्त ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय पाल मलिक को 4 एम्बुलेंस डेस्टिनेशन पर तैनात करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

कानूनी व्यवस्था के लिए डीएसपी मुख्यालय सत

ट्रेड यूनियन्स का दावा-25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर

बैंक-डाकघर में काम बंद रहेगा, परिवहन सेवाएं ठप हो सकती है

नई दिल्ली ।

बैंकिंग, इंश्योरेंस से लेकर कोल माइनिंग, हाईवे और कंस्ट्रक्शन में लगे 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। देश भर में होने वाले इस व्यापक हड़ताल से जरूरी सेवाओं का प्रभावित होना तय है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी इकाइयों के एक ग्रुप ने 'सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों का विरोध करने' के लिए इस आम हड़ताल या भारत बंद का आह्वान किया है। श्रमिक संगठनों के इस ग्रुप ने 'देशव्यापी आम हड़ताल को व्यापक रूप से सफल' बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक/असंगठित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हड़ताल के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

इन क्षेत्रों पर पड़ेगा हड़ताल का सीधा असर

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा, ''हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देशभर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे।'' हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी। ग्रुप ने बयान में कहा कि पिछले साल ग्रुप ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा था। ग्रुप ने कहा कि सरकार पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं कर रही है और श्रमबल के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है।

क्या है कर्मचारियों की मांग

बयान में कहा गया है, ''हम सरकार से बेरोजगारी पर ध्यान देने, स्वीकृत पदों पर भर्ती करने, ज्यादा नौकरियों के सृजन, मनरेगा श्रमिकों के कार्य दिवसों एवं मजदूरी में बढ़ोतरी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी समान कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ईएलआई (रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना लागू करने में व्यस्त है।'' ग्रुप ने ये भी आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में युवाओं को नियमित नियुक्तियां देने के बजाय सेवानिवृत्त लोगों को ही काम पर रखने की नीति देश की वृद्धि के लिए हानिकारक है क्योंकि 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और बेरोजगारों की संख्या 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक है। सरकारी विभाग और कंपनियों के दिया हड़ताल में शामिल होने का नोटिस

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देशभर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे।

एनएमडीसी लिमिटेड और अन्य गैर-कोयला खनिज, इस्पात, राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के श्रमिक नेताओं ने भी हड़ताल में शामिल होने का नोटिस दिया है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर लामबंदी करने का फैसला किया है। श्रमिक संगठनों ने इसके पहले 26 नवंबर, 2020, 28-29 मार्च, 2022 और पिछले साल 16 फरवरी को भी इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल की थी।

मुख्यमंत्री सीएम नीतीश का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान

सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35फीसदी आरक्षण

पटना ।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यानी महिला आरक्षण में डोमिसाइल का प्रावधान कर दिया गया है. किसी भी सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35फीसदी सीटें बिहार की महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहेंगी. बता दें बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा.

राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

एएआईबी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी

एयर इंडिया विमान हादसा

नई दिल्ली । विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है. रिपोर्ट ब्यूरो के शुरुआती आकलन और जांच के शुरुआती चरण में जुटाई गए निष्कर्षों पर आधारित है. हालांकि, रिपोर्ट में क्या है, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. जांच रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट इस सप्ताह के अंत में सार्वजनिक की जा सकती है. हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या है, ये सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दुर्घटना के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के 32 सेकंड के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस भयानक दुर्घटना के पीड़ितों में से एक थे. इस त्रासदी में केवल सीट 11 पर बैठा एक व्यक्ति बच गया था. इससे पहले लंदन की एक कानूनी फर्म ने कहा कि अहमदाबाद से ब्रिटेन की राजधानी के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई विमान दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले कई ब्रिटिश परिवारों ने जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद की स्थिति में गंभीर सवालों के जवाब के लिए औपचारिक रूप से उसे नियुक्त किया है. बता दें कि लंदन जाने वाला एयर इंडिया का एक विमान 12 जून को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेघाणीनगर इलाके में एक छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही छात्रावास के भी कुछ लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी.

थप्पड़ कांड की गूंज... ठाणे में भाषा विवाद विरोध रैली के लिए सड़कों पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में

मुंबई । मुंबई में हुए थप्पड़ कांड की गूंज महाराष्ट्र की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है. मनसे कार्यकर्ता अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कई कार्यकर्ताओं को ठाणे के मीरा रोड पर उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब वे मुंबई में हुए थप्पड़ कांड के विरोध में मार्च निकाल रहे थे. इस घटना में मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक पर हमला कर दिया था. मनसे कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने और पुलिस द्वारा उन्हें पकड़कर पुलिस वैन में डालने के दौरान ड्रामेटिक सीन सामने आए. दरअसल, पुलिस ने आज के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी. लेकिन फिर भी मनसे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए. हिरासत में लिए जाने के दौरान, कई मनसे कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि व्यापारियों को थप्पड़ की घटना के खिलाफ विरोध करने की अनुमति क्यों दी गई उनमें से कई ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी चाहिए और धमकी दी कि जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग की दो टूक, कहा- यह पूरी तरह समावेशी प्रक्रिया

नई दिल्ली ।

बिहार की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर तगड़ा हमला बोला है। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह समावेशी है। इसमें सब कुछ समाहित किया गया है। इसे लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। दरअसल, विपक्ष ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन या गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी (शरद

पवार गुट), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के नेताओं ने मामले में मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई अन्य याचिकाएं भी इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।

गणना फॉर्म 7.69 करोड़ या 97.42 प्रतिशत मतदाताओं को बांटे गए

शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सभी को शामिल करने वाली है। यह बिहार के मौजूदा 7,89,69,844 मतदाताओं तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता का नाम, पता, पुरानी फोटो आदि विवरण के साथ पहले से भरे हुए गणना फॉर्म हर मौजूदा मतदाता को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से भरे हुए गणना फॉर्म 7.69 करोड़ या 97.42 प्रतिशत मतदाताओं को बांटे गए हैं। बूथ स्तर के अधिकारी भरे हुए गणना फॉर्म एकत्र करने के लिए हर घर में कम से कम तीन बार जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए।

पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा

उन्होंने बताया कि पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है। कई मतदाताओं का निधन हो चुका है या वे स्थानांतरित हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। गणना फॉर्म जमा करने वाले सभी लोगों को 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उन सभी मतदाताओं को शामिल करके मसौदा मतदाता सूची तैयार करेंगे, जिनके गणना फॉर्म 25 जुलाई से पहले प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जोर दिया कि 1 सितंबर को समाप्त होने वाली दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान पात्रता दस्तावेज अलग से भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार है, जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 के साथ पढ़ा जाए।

कानून व्यवस्था को लेकर खड़गे का जेडी(यू)-बीजेपी पर वार

बिहार बना देश का क्राइम कैपिटल

नई दिल्ली । कांग्रेस ने मंगलवार को बिहार की डबल इंजन सरकार पर राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नष्ट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में बदलाव निश्चित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जेडी(यू)-बीजेपी गठबंधन ने बिहार को देश की अपराध राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था तबाह कर दी है। पिछले 6 माह में 8 बिजनेसमैन की हत्या, 5 बार पुलिस की पिटाई हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कल ही अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को मारा गया। मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा! जदयू और भाजपा ठगबंधन ने बिहार को देश की «क्राइम कैपिटल» बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खुद के आँकड़े बताते हैं कि बिहार में गरीबी चरम पर है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और लुप्त कानून व्यवस्था के चलते, निवेश केवल कागज़ों तक सीमित रह गया है। इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि अब वो बीमार नहीं रहेगा! बिहार में बदलाव तय है। इंडिया गठबंधन इस बदलाव को लाकर रहेगा। पिछले सप्ताह पटना में अपने आवास के बाहर प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या के बाद विपक्ष एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को «भारत की अपराध राजधानी» बना दिया है। गांधी ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में वोट केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को बचाने के लिए होगा।

गुंडागर्दी ही एकमात्र उद्देश्य

राज ठाकरे पर फिर भड़के निशिकांत दुबे; कहा- इस बात से डरते हैं एमएनएस चीफ

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला। यह बयान राज्य में हिंदी-मराठी भाषा विवाद के बीच मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कथित हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के सामने आने के बाद आया है। निशिकांत दुबे ने 2007 की एक घटना का हवाला दिया, जिसका कथित तौर पर क्विकीलीक्स में जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि मनसे कार्यकर्ताओं ने बिहार के एक छात्र पर हमला किया। दुबे ने कहा कि गुंडागर्दी ही राज ठाकरे का एकमात्र उद्देश्य है और वह यह सब मुंबई नगर निगम चुनाव हार के डर से करते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा, जब राज ठाकरे को जन समर्थन नहीं मिलता, तो वह अपने गुंडों को आगे कर देते हैं। इसका मतलब है कि गुंडागर्दी ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, जो वे मुंबई नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हार के डर से करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरा विरोध ठाकरे की गुंडागर्दी को लेकर है और अब सहनशीलता की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं।

पुलिस ने कारोबारी अशोक साव को किया गिरफ्तार

पटना । बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। उसपर गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पटना सिटी से गिरफ्तार शूटर विजय सहनी से पूछताछ के बाद पुलिस को अशोक साव के खिलाफ कई सबूत मिले थे। वह नालंदा का रहने वाला है। पुलिस ने छापेमारी कर अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अशोक साव से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो अशोक साव बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन लाइन में कारोबार करता था। इसी कारोबार को लेकर उसकी गोपाल खेमका से विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद उसने गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। इसके बाद उसने गोपाल खेमका को मारने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी। प्रोफेसनल शूटर हायर किए। इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिलवाया।इधर, पटना पुलिस की एक टीम ने पहले ही विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि, उसके परिजन उसे निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि विकास चेन्नई में जॉब करता था। उसका इनसब से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन, पुलिस ने उसे बलि का बकरा बना दिया। पुलिस की गोली का शिकार हुए विकास की मौत के बाद उसकी मां ने कहा कि विकास ने कुछ नहीं किया है। वह पूरी तरह निर्दोष है। घटना के बाद विकास के घर में मातम पसरा है।

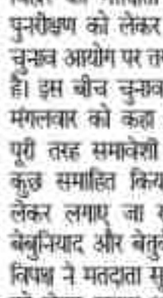

छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर गरजा बुलडोजर, सीएम बोले- सभी अपराधियों की संपत्तियां होंगी जब्त

लखनऊ ।यूपी एटीएस ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने के आरोपी में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है. इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी. उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने. सीएम योगी का रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब बलरामपुर में जलालुद्दीन के घर पर

बुलडोजर एक्शन हुआ है. सीएम योगी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन-बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं. उन्होंने आगे लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी. आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है. उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी, जो समाज के लिए एक उदाहरण बने. धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बलरामपुर स्थित घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है.

यूपी एटीएस ने एक संगठित धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए खुद को सूफी संत बताने वाले छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरोह पर विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति खरीद, प्रेमजाल और प्रलोभन के जरिए सैकड़ों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है.

उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ अमिताभ यश ने बताया था कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन खुद को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है. जानकारी मिली थी कि वह बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था. इसकी जांच एसटीएफ ने की. ग्रुप के एजेंट युवाओं को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते हैं. इसके अलावा नाबालिगों का भी धर्मांतरण गैंग द्वारा करवाया गया. इनके 40 खातों में विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया.

इंस्टाग्राम वाली लव स्टोरी निकली ठगी की चाल, शादी का झांसा देकर लूट लिया सोना, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के साउथ-ईस्ट इलाके के शाहीन बाग थाना पुलिस ने एक ऐसी चौंकाने वाली ठगी का खुलासा किया है. जिसमें एक युवक ने इंस्टाग्राम पर प्यार और शादी का झूठा सपना दिखाकर एक युवती से लाखों के सोने के गहने ठग लिए. लेकिन जैसे ही युवती को ठगी का एहसास हुआ उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने उसे दबोच कर इस पूरे ठगी का पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान, सैफीउल्लाह उर्फ सैफ के रूप में हुई है. वह यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और शाहीन बाग में किराए पर रह रहा था. उसके पास से पुलिस ने ठगे गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं. डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा के मुताबिक, शिकायतकर्ता युवती ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 45 दिनों से इंस्टाग्राम पर सैफ नाम के व्यक्ति के संपर्क में थी. बातचीत जल्द ही दोस्ती में बदली और दोनों ने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए. सैफ ने शादी का वादा कर उसके विश्वास को जीता और भावनात्मक रूप से उसे अपने जाल में फंसा लिया. युवती ने बताया कि, 2 जुलाई, 2025 को सैफ ने युवती से संपर्क कर अपने पिता की बीमारी का हवाला देकर आर्थिक मदद मांगी. जब युवती ने कहा कि उसके पास नकदी नहीं है, क्योंकि उसके परिवार ने हाल ही में उसकी शादी के लिए गहने बनवाए हैं, तो सैफ ने दो दिनों के लिए गहने उधार देने की गुहार लगाई. उसने भरोसा दिलाया कि वह गहनों को गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम करेगा और जल्द ही उन्हें वापस कर देगा. जिस पर शिकायतकर्ता युवती ने 2-3 जुलाई की रात, अपने माता-पिता को बिना बताए अलमारी से करीब 80 ग्राम (लगभग 8 तोला) सोने के आभूषण निकाले और सैफ को दे दिए. जिसके बाद आरोपी ने युवती के कॉल्स और मैसेज से दूरी बनानी शुरू कर दी. संदेह होने पर युवती ने अपनी मां को सारी बात बताई और फिर शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.डीसीपी ने बताया कि, मामले की जांच और आरोपी की पकड़ के लिए इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल तेजेंद्र सिंह और कांस्टेबल गौरव की एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त सूत्रों की मदद से आरोपी सैफीउल्लाह उर्फ सैफ (23) की पहचान की और उसे दबोच लिया. उसके पास से सोने की 04 चूड़ियां, एक जोड़ी झुमके, सोने की चेन, एक पेंडेंट, एक अंगूठी और एक जोड़ी कान की बालियां बरामद की गईं. पूछताछ में सैफ ने बताया कि वह मूलतः उत्तर प्रदेश के बिजनौर का निवासी है और शाहीन बाग में किराए के मकान में रह रहा था. वह एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता है लेकिन वह अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था. इसलिए उसने युवतीवती को बहला-फुसलाकर गहने लेने की योजना बनाई ताकि उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सके. इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.